

लोक सभा चुनाव और एक पूर्व समीक्षा

अगले आम चुनाव को तीन महीने शेष बचे हैं। अनेक पाठक भी जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिये, और मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूँ कि चुनावों के पूर्व एक समीक्षा प्रस्तुत करूँ। वैसे तो पूरी दुनियां में ही राजनीति समाज व्यवस्था को प्रभावित करती है, किन्तु भारत की स्थिति तो अन्य देशों की अपेक्षा कुछ इतनी अलग है कि यहाँ राजनीति समाज व्यवस्था को प्रभावित ही नहीं करती बल्कि संचालित भी करती है। इसलिये हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी अपने विचार प्रस्तुत करें।

भारतीय राजनीति में चार बातें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं— 1. परिवार केन्द्रित 2. व्यक्ति केन्द्रित 3. दल केन्द्रित 4. विचार धारा केन्द्रित। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में घुमा फिराकर एक ही परिवार का वर्चस्व रहा, जिसने भले ही अपना नाम कांग्रेस रखा हो किन्तु उसमें न कांग्रेस का कुछ लेना देना रहा न किसी व्यक्ति का, और न ही किसी विचार धारा का। सुविधानुसार जब चाहा तब समाजवादी बन गये और जब चाहा तब पूँजीवाद की राह पकड़ ली और यदि कभी जरूरत पड़ी तो तानाशाह बनने में भी परहेज नहीं किया। किन्तु इनकी सारी तिकडम, सत्ता को अपने परिवार तक सीमित करने में लगी रही। आज दुनिया इतनी आगे निकल गई है, भारत भी अनेक मामलों में आगे बढ़ा है, राजनीति में भी अनेक नये-नये प्रयोग हो रहे हैं, किन्तु यह परिवार आज भी सत्ता को अपने परिवार तक सीमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस को छोड़कर अधिकांश राजनैतिक दल व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति ही विचार धारा भी है, राजनैतिक दल भी है और परिवार भी। इनमें जनता दल युनाइटेड तथा संघ संचालित दल को छोड़कर बाकी सब दल शामिल हैं। लालू, मुलायम, मायावती सरीखे सारे दल तो हैं ही, किन्तु वामपंथी दल भी इससे कहीं ज्यादा दूर नहीं हैं। तीसरे प्रकार के वे समूह हैं जो राजनैतिक दल के रूप में स्थापित हैं। इनमें पहले तो जेडीयू तथा भाजपा आते रहे हैं, किन्तु अब भाजपा के समाप्त होकर संघ परिवार के सामने आ जाने के बाद अकेला जेडीयू बचा है, जिसका अस्तित्व भारतीय राजनीति में न के बराबर बचा है। चौथा समूह विचारधारा केन्द्रित है जिसमें संघ परिवार तथा कुछ-कुछ वामपंथियों को भी माना जा सकता है, जो दोनों विपरीत विचारधाराओं पर केन्द्रित हैं। वर्तमान चुनावों में तो ऐसा दिखता है कि संघ परिवार ने भी मोदी के नाम पर अपना सारा दांव लगा दिया है। यदि विचारधारा के नाम पर हम भारत की सम्पूर्ण राजनीति की समीक्षा करें तो एक तरफ वे दल आते हैं जो घोषित रूप से तानाशाही के पक्षधर हैं दूसरी ओर वे दल हैं जो घोषित रूप से तो लोकतंत्र के पक्षधर हैं किन्तु हैं दुलमुल। संघ परिवार और उनके चेहरे नरेंद्र मोदी घोषित रूप से तानाशाही के पक्षधर हैं क्योंकि संघ परिवार की घोषित नीतियों में केन्द्रित राजनीति सबसे उपर है। साम्यवादी पार्टियां भी नीतिगत रूप से लगभग तानाशाही के पक्षधर हैं यद्यपि वे भारतीय राजनीति की चर्चा से बाहर हो चुकी हैं। अन्य सभी राजनैतिक दल दुलमुल विचारधारा के हैं, क्योंकि उनकी कोई घोषित विचारधारा नहीं है। जेडीयू को थोड़ा अवश्य भिन्न माना जा सकता है, वह भी अब चर्चा से बाहर ही दिख रही है।

कुछ समय पूर्व तक पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था, कि हमारे समक्ष परिवार और तानाशाही के बीच एक को चुनने की मजबूरी है। दुनिया जानती है कि लोकतंत्र एक असफल सिद्धान्त है जो तानाशाही की जगह मजबूरी में स्वीकार किया जाता है। किन्तु यदि लोकतंत्र लोकस्वराज्य की दिशा में न जाये तो वहाँ अव्यवस्था होना निश्चित है, जैसा कि भारत सहित अनेक दक्षिण एशियाई देशों में स्पष्ट दिख रहा है। स्वतंत्रता के बाद एक परिवार ने अपने स्वार्थवश लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में नहीं बढ़ने दिया। अन्य राजनैतिक दल भी उसी स्वार्थ में सत्ता परिवर्तन के प्रयत्नों तक सीमित रहे। उन्होंने कभी भी लोकतंत्र को लोकस्वराज्य की दिशा देने की बात नहीं सोची क्योंकि यह प्रयत्न तो उनके पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। लोकतंत्र का जो परिणाम होना था वही हुआ कि भारत अव्यवस्था की दिशा में बढ़ता चला गया। देश तरक्की किया समाज नीचे गिरते चला गया। भौतिक उन्नति तो बहुत हुई किन्तु चरित्र पतन भी उतनी ही गति से बढ़ता चला गया। एक बार जयप्रकाश जी के प्रयत्नों से आशा की एक किरण दिखी थी किन्तु वह भी सत्ता परिवर्तन तक आकर सिमट गई। दूसरा प्रयत्न अब अन्ना हजारे ने किया था जो न सत्ता परिवर्तन की दिशा में बढ़ पाया, न व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में। अब वह प्रयत्न अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में

कुछ-कुछ बढ़ रहा है, पता नहीं किस दिशा में जायेगा ? अव्यवस्था का सिर्फ एक ही समाधान होता है और वह है तानाशाही। भारतीय राजनीति की अव्यवस्था से परेशान होकर यहाँ के लोगों ने तानाशाही को भी स्वीकार करने का मन बना लिया है। जिसका स्पष्ट आभाष संघ परिवार और नरेंद्र मोदी की तूफानी बाढ़ में दिखाई देता है।

यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर दलों का ऑकलन करें, तो नीतियाँ बनती हैं विचारों के आधार पर, और कार्य होता है और संस्कारों के आधार पर। इसका अर्थ यह हुआ कि विधायिका में अधिक से अधिक विचारवान लोग होने चाहिए भले ही चरित्र का मापदण्ड औंशिक रूप से कमजोर भी क्यों न हो। दूसरी ओर कार्यपालिका में ईमानदार लोगों का बहुमत होना चाहिए, अर्थात् कार्यपालिका में चरित्र महत्वपूर्ण है, वैचारिक दृष्टि से औंशिक कमजोरी भी चल सकती है। इस मामले में नरेंद्र मोदी या संघ परिवार बहुत पीछे हैं, क्योंकि वे संस्कारों पर जोर देते हैं, जिसका अंतिम परिणाम होता है चरित्र और विधायिका की आवश्यकता है विचार प्रधान लोगों की। इस मामले में साम्यवादियों का भी अलग सोच नहीं है। संघ परिवार इस संस्कार से जुड़ा हुआ है कि जो कुछ पुराना है वही अच्छा है जबकि साम्यवाद इस संस्कार में जुड़ा हुआ है कि जो कुछ पुराना है वह गलत है। वास्तविकता यह है कि लोकतंत्र में विधायिका को देश, काल, परिस्थिति अनुसार स्वतंत्र विचार करने की आदत डालनी चाहिए। इस मामले में राहुल गाँधी की भूमिका सबसे अच्छी है। मैं तो तब से उनका और अधिक प्रशंसक हो गया जब से काँग्रेस पार्टी के जिम्मेदार समूह ने जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की वकालत शुरू कर दी है। अब तक सिर्फ मुलायम सिंह ने डरते-डरते हल्की सी यह बात कही है, अन्यथा अन्य राजनैतिक दल जिनमें संघ परिवार भी शामिल है, इस बात को समझते हुए भी तथा सहमत होते हुए भी इसके विपरित ही बोलते रहते हैं। काँग्रेस पार्टी ने यह खतरा उठाकर एक बहुत अच्छा काम किया है।

काँग्रेस पार्टी ने राहुल गाँधी के नेतृत्व में अवश्य ही कुछ-कुछ लोकतंत्र को लोकस्वराज्य की दिशा में मोड़ने की बातें शुरू की किन्तु ये बातें बहुत देर से शुरू हुईं और दूसरा इस परिवार पर भारत की जनता का अब कोई विश्वास नहीं रहा। इसलिए ईमानदार प्रयत्न होने के बाद भी भारत की जनता अब इन पर विश्वास नहीं कर रही। ऐसे समय में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर अरविंद केजरीवाल का अभ्युदय एक आशा की किरण जगाता है। अरविंद केजरीवाल के भी क्रिया-कलाप बिलकुल साफ नहीं है। उनमें भी व्यक्ति केन्द्रित राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है। उनमें भी सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का घालमेल साफ दिखाई देता है किन्तु अब तक अरविन्द केजरीवाल और उनके दल में न तो कोई तानाशाही की अवधारणा दिखी है न कोई परिवारवाद की। इतना अवश्य है कि इस दल की भी कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं है, किन्तु इतना अवश्य है कि या तो वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही आगे बढ़ेगी अथवा लोकतंत्र औंशिक रूप से लोकस्वराज्य की दिशा में झुकेगा।

चुनावों को सिर्फ दो-तीन महीने ही बचे हैं, अरविन्द केजरीवाल के दल को भी प्रकाश में आये एक महीना ही बीता है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी और संघ परिवार को महसूस होने लगा है कि जेल में जन्म लेने वाला बालक हो सकता है कृष्ण ही हो। संघ परिवार और नरेंद्र मोदी भी इस अकस्मात घटना से चिंतित हैं और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। काँग्रेस पार्टी की स्थिति सॉप-छछुन्दर की हो गई है। उसे न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। उसे अपना पराभव तो निश्चित दिखता है किन्तु वह सोच नहीं पा रही है कि अरविन्द केजरीवाल के साथ होकर अपनी थैड़ी-मोड़ी साख बचा लें या अन्त तक लडते-लडते शहीद हो जाएं।

काँग्रेस पार्टी को यह तो आभाष हो चुका है कि सत्ता में बने रहना असंभव है। काँग्रेस पार्टी ने सोचा था कि उसकी चुनाव पूर्व की गई कुछ अच्छी घोषणाएँ उसे जन विश्वास दिला सकेंगी, किन्तु एक तो उसने परिवार केन्द्रित राजनीति से बाहर निकलने का निर्णय नहीं किया, दूसरे उसने राहुल गाँधी सरीखे एक संत हृदय राजनीति के अनाडी खिलाड़ी पर अपना दाँव लगाया और तीसरे उसने परिवार मोह में पडकर मनमोहन सिंह को इस सीमा तक बदनाम कर दिया कि मनमोहन सिंह की असफलता उनके स्वयं के गले की हड्डी बन गई। फिर भी अभी यह परिवार दौड़ से बाहर होने को तैयार नहीं है। जिसका अर्थ हुआ कि भले ही हम डूबें तो डूबें किन्तु हम डूबने के पहले किसी और को आगे क्यों आने दें। चुनाव पूर्व सोनिया गाँधी की अब तक की सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं और अब तो सिर्फ दो-तीन महीने ही बचे हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट दिखता है कि लडाईं नरेंद्र मोदी

बनाम अन्य के बीच ही होने वाली है, जिसके अंतिम परिणाम के रूप में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। स्पष्ट दिखता है कि एक तरफ संघ परिवार और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी है तो दूसरी तरफ अनेक स्वार्थी राजनेताओं का संयुक्त समूह। नरेंद्र मोदी अभी सबसे आगे दिख रहे हैं जिनकी गति बहुत तेज है, फिर भी वे चुनाव तक कहाँ तक निकल पाएंगे यह पता नहीं।

फिर भी अब हमारे पास भी इतना समय नहीं बचा है कि हम अपनी सलाह देने के लिए और अधिक प्रतीक्षा करें। मेरे विचार में भूलकर भी कॉंग्रेस पार्टी को वोट देना परिवारवादी गुलामी को स्वीकार करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को वोट देना भी कुँ से निकलकर खाई में गिरने सरीखे होगा, क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी के पास समस्याओं का समाधान है तो गुलामी का खतरा भी है। अन्य दलों के पास गुलामी का खतरा तो नहीं है, किन्तु समस्याओं का समाधान भी नहीं है। ऐसे समय में अरविन्द केजरीवाल का व्यक्तित्व अथवा उनका दल ही एकमात्र ऐसा विकल्प दिखता है, जिसे वोट देकर आत्म-संतुष्ट हुआ जा सकता है। मैं जानता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल की स्वतः अथवा किसी अन्य को प्रधानमंत्री बनाने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। मैं यह भी जानता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल को वोट देने का मतलब वोट को समुद्र में डाल देने जैसा है। किन्तु मेरा यह अवश्य मानना है कि अरविन्द केजरीवाल को दिया गया वोट भविष्य की आत्मग्लानि से अवश्य बचाएगा कि मैं किसी परिवार या किसी तानाशाह का समर्थन करने के पाप में भागीदार नहीं हूँ। अरविन्द केजरीवाल को दिया गया वोट निरर्थक भी हो सकता है और सार्थक भी किन्तु इतना निश्चित है कि वह वर्तमान राजनैतिक दिशा को इसी तरह आगे बढ़ने में सहायक तो नहीं होगा। मेरी अरविन्द केजरीवाल जी को भी सलाह है कि वे धीरे-धीरे लोकस्वराज्य की दिशा में एक-एक कदम बढ़ते हुए दिखें, जिससे हम सब और अधिक विश्वासपूर्वक अपनी बात को कह सकें।

1. जगदीश गाँधी :- सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनऊ उत्तर-प्रदेश

प्रश्न:- आप द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में आपने लिखा है कि शिक्षा का चरित्र से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, बल्कि सच बात तो यह है, कि शिक्षा क्षमता का विकास करती है, चरित्र का नहीं। इस संबंध में हमारा आपसे निवेदन है कि मनुष्य की तीन वास्तविकताएँ होती हैं—1. मनुष्य एक भौतिक प्राणी है। 2. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और 3. मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है और यदि मनुष्य की इन तीनों वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, परिवार और स्कूल में मिली हुई शिक्षा के द्वारा बच्चे का बचपन से ही संतुलित विकास किया जाता है, तो बालक अच्छा, चरित्रवान और विचारवान बनेगा।

हमारा यह भी मानना है कि किसी भी मनुष्य के तीन चरित्र होते हैं। पहला चरित्र प्रभु प्रदत्त दूसरा माता-पिता के जीन्स, वंशानुकूल से प्राप्त चरित्र तथा तीसरा परिवार स्कूल तथा समाज से मिले वातावरण से विकसित या अर्जित चरित्र। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण तीसरे अर्थात् अर्जित चरित्र होते हैं। इस अर्जित चरित्र का निर्माण बालक को परिवार, विद्यालय व समाज में मिले गुण व अवगुण पर निर्भर करता है। उसे जिस प्रकार की शिक्षा परिवार, विद्यालय तथा समाज से मिलती है, वैसा ही उसका चरित्र भी निर्मित हो जाता है। वास्तव में मानव जाति का भविष्य इन्हीं तीन क्लास रूमों 1. परिवार 2. विद्यालय तथा 3. समाज में मिली शिक्षा के द्वारा ही गढ़ा जाता है। इस पत्र के साथ मैं अपना एक लेख "प्रत्येक बच्चे को सारी मानव जाति की सेवा के लिये तैयार करें" आपको प्रेषित कर रहा हूँ। कृपया जनहित में इस लेख को ज्ञानतत्व के अगले अंक में प्रकाशित करने की कृपा करें। इस कृपा के लिये हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे।

उत्तर:- मैं आपसे सहमत हूँ कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी भी है, किन्तु आध्यात्मिक प्राणी है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। संभव है कुछ लोग आध्यात्मिक हों तथा कुछ लोग ना हों। समाज तथा परिवार से प्राप्त शिक्षा उसके चरित्र निर्माण में बहुत सहायक होती है, किन्तु स्कूल से प्राप्त शिक्षा चरित्र पर प्रभाव डालती है, ऐसा स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार से बालक के अन्य माध्यमों से प्राप्त चरित्र स्कूली शिक्षा के द्वारा विकसित होता है। यदि सद्चरित्र की दिशा में बीजारोपण होगा, तो स्कूली शिक्षा उस अंकुरित बीज का विस्तार करेगी। किन्तु यदि बीजारोपण ही दुष्चरित्र के रूप में हुआ तो स्कूली शिक्षा उस दुष्चरित्र के बीज को सद्चरित्र में नहीं बदल सकेगी। आपने चरित्र के तीन आधार बताये हैं—1. प्रभुप्रदत्त 2. माता-पिता के

जीन्स से प्राप्त तथा 3. स्कूल और समाज से प्राप्त। मैं प्रभूप्रदत्त चरित्र के पक्ष-विपक्ष में कहने की स्थिति में नहीं हूँ, साथ ही मैं समाज और विद्यालय को एक साथ जोड़ कर नहीं देखता। फिर भी आप जैसे विद्वान ने लिखा है, तो मैं इस पर फिर से विचार करूँगा। आपने जो लेख लिखा है, कि प्रत्येक बच्चे को सारी मानव जाति की सेवा करने के लिए तैयार करें-इस लेख से मेरी सहमति है तथा इस लेख में समीक्षा के लिए कुछ नहीं है इसलिए यह लेख छापना उचित नहीं है।

2. ओमप्रकाश मंजुल- पूरनपुर पीलीभीत, उ.प्र.।

प्रश्न:1—आदमी को पतित और नंगा करती मंहगाई :—मंहगाई आज देश की प्रमुख विकराल और ज्वलंत समस्या है। प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने भी 3.01.14 की अपनी प्रेस वार्ता में इसे स्वीकारा है। मंहगाई भ्रष्टाचार का कारण भी होती है और परिणाम भी। डकैती को छोड़ भी दे तो चोरी उठाईगीरी राहजनी आदि मंहगाई के ही बच्चे हैं। देश में व्याप्त मंहगाई को देखकर प्रथम विश्वयुद्ध 1914-19 के ठीक बाद पैदा हुई मंहगाई की याद आ रही है। यूँ वह मंहगाई इंग्लैंड, इटली, फ्रांस आदि यूरोप के सभी देशों में संव्याप्त थी। पर जर्मनी में तूफानी गति से बढ़ रही मंहगाई का रूप सर्वाधिक था। वहाँ चाय पीते-पीते चाय की कीमत दो-तीन गुनी हो जाती थी। लोग होटल और रेस्ट्रॉ में, एक साथ ही दो-तीन चाय का आर्डर एक बार में ही दे देते थे, ताकि इस बीच एक-दो और मित्रों के आ जाने पर बढ़े हुए अतिरिक्त पैसे न देने पड़े। यह वह समय था, जब एक घंटे में ही फीतों का मूल्य जूतों के मूल्य के बराबर हो जाता था। बढ़ते मुद्रा प्रसार याने मंहगाई का दोधारा दोष यह भी होता है कि इसमें निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन तथा धनिक वर्ग और अधिक धनी हो जाता है। फलतः धनी और निर्धन के बीच की खाई और अधिक बढ़ जाती है। इस तथ्य को इस एक ही उदाहरण से समझा जा सकता है—डीजल का मूल्य यदि दो रुपया प्रति लीटर बढ़ता है, तो बस मालिक पूंजीपति आठ रुपये से बढ़ाकर दस रुपये किराया कर देता है। डीजल की बढ़ी कीमत का बहाना बनाकर वह सौ यात्रियों से दो सौ रुपये अतिरिक्त लेता है, जबकि यात्रा में प्रयुक्त दो लीटर डीजल पर बस मालिक की जेब से केवल चार रुपये ही ज्यादा निकले हैं। इस प्रकार पहले से ही धनी बस मालिक और अधिक मालदार हो जाता है तथा पहले से ही निर्धन यात्री और गरीब हो जाते हैं। ऐसे ही असीम सम्पत्ति से असीम शक्ति पाकर हिटलर, मुसोलिनी और नैपोलियन जैसे तानाशाह पैदा होते हैं। दूसरी ओर गरीबी में लाज बचाने के प्रयत्न में नैतिकता की चादर ऐसी तार-तार हो जाती है, कि लाज कब चली गयी, पता ही नहीं चलता। वित्त भर कपड़ा से ही लज्जाजनक अंग ढँक जाये तो मीटर भर कपड़ा क्यों खरीदा जाये ? निर्धन क्रेता चाहे वह आदमी हो या औरत की नियतिजनित यह भी आदत बन जाती है, कि वह विक्रेता के समक्ष बहुत झुक कर और समर्पित होकर पेश आते हैं भले ही दुकानदार उँची दुकान पर बैठा दवाई, कपड़ा, साबुन आदि बेच रहा हो या गली में चिल्ला-चिल्ला कर आलू, मूली, प्याज बेच रहा हो। धीरे-धीरे निर्लज्जता स्वभाव बनते हुए शान और फैशन का प्रतीक बन जाती है। यही नहीं अनैतिकता से असम्बद्ध लोगों को पिछड़ा और पोंगापंथी तथा अनैतिक लोगों को प्रगतिशील एवं उन्नत मानने की प्रवृत्ति पनपने लगती है। नतीजतन समाज में नंगा नाच प्रदर्शित करने की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जर्मनी में यही हुआ—प्रथम महायुद्धोत्तर काल की अनैतिकता का हाल बयां करने वाली स्टेफेन और वेसिंग की कृति की कुछ पक्तियाँ— “प्रत्येक लडकी अपनी अशुद्धता की सगर्व गप्प हाँकती थी। उस समय बर्लिन के हर विद्यालय में इसे शान के खिलाफ माना जाता था, कि कोई लडकी सोलह वर्ष की होकर भी अभी तक असंभुक्त है। हर लडकी अपने सम्भोग कर्म को दूसरी की तुलना में कहीं अधिक अच्छा और निराला बताने को उत्सुक रहती थी”। आज के औसत भारतीय समाज की नैतिक स्थिति भी इससे अत्यधिक अच्छी नहीं है। “रहें घरी चाहे बुने दरी” को चरितार्थ करने वाले घर-घुस्सू और कूप-मण्डूक भले ही इस बात से सहमत न हों, पर प्रतिदिन रेल, बस और मोटर आदि से सफर करने वाले तथा स्कूल-कालेज के लडके-लडकियों एवं मिलो-कारखानों और कार्यालयों में कार्य करने वाली किशोरियों को देखने-जानने वाले इस तथ्य से अवश्य सहमत होंगे।

काँग्रेस के अन्तिम इन दो कमिक कालों में नून-तेल, लकड़ीयाँ जैसी जरूरी चीजों तथा नाई, दर्जी, मोची, रिक्शा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि आवश्यक सेवाओं की कीमतें दस गुना बढ़कर जिस उंचाई तक पहुंच चुकी है, उसने आम आदमी का जीना

दूबर कर दिया है। चार-पांच हजार रूपया तोला बिकने वाला सोना जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का मापक है आज तीस-हजारी बन चुका है। इसके बाद मंहगाई की भयावहता का अहसास कराने के लिये कुछ नहीं बचता ।

2-3 वर्ष पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना के अनशन पर लाखों लोगों के एकत्रीकरण में मुख्य भूमिका मंहगाई की ही थी। मजदूर, कृषक, आम आदमी को भ्रष्टाचार या लोकपाल का मतलब न उस समय मालूम था न आज मालूम है, और न ही इससे विशेष मतलब है। पर वही मंहगाई को भली-भौति जानता है क्योंकि मंहगाई ने उसे बुरी तरह से पीटा है। आम-जन को लगा कि अन्ना की आवाज उसे मंहगाई से निजात दिलायेगी। इसलिये उसने अन्ना की आवाज से आवाज मिलायी थी। हाल के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मंहगाई की अहम भूमिका रही है। यदि केन्द्र सरकार आगामी 4-5 महीनों में मंहगाई नियंत्रण में विफल रहती है तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस को काफी मंहगा पड़ेगा।

उत्तर— ऐसा लगता है कि आप सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं जिससे प्रभावित होकर आप मंहगाई के अस्तित्व को स्वीकारने लगे हैं, जबकि मेरी मान्यता है कि—मंहगाई के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पूरी तरह भ्रमपूर्ण है। यदि दुनिया के करोड़ों लोगों ने पृथ्वी को चपटी कहकर उसे गोल कहने वाले विद्वान को फॉसी पर चढ़ा दिया, तो क्या पृथ्वी गोल नहीं हुई ? मैंने ज्ञानतत्व-192, 183 तथा 158 में विभिन्न समयों पर तर्क संगत तरीके से मंहगाई के अस्तित्व को अस्वीकार किया, जिसमें से एक ज्ञानतत्व 158 का लेख विचारार्थ आपके पास जा रहा है। अन्य स्थानों पर भी कई बार मैंने मंहगाई के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। किन्तु आज तक किसी ने मेरे कथन का तर्क संगत प्रश्नोत्तर नहीं किया। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मंहगाई से सब लोग त्रस्त हैं। यदि सब लोग भूतों से त्रस्त महसूस करने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ ? आप हर विषय पर गंभीरता से विचार करते हैं, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे तर्कों के विरुद्ध अपने तर्क देंगे, जिससे या तो मैं कुछ समझूँगा या आप कुछ समझेंगे। यदि आपके पास मंहगाई संबंधी प्रकाशित ज्ञानतत्व उपलब्ध नहीं हों तो आप लिखिएगा मैं वे भी आपको भेज दूँगा। ज्ञानतत्व 158 ,अगस्त 2008 अंक में प्रकाशित लेख इस प्रकार था।

मंहगाई का भूत—आज पूरे भारत में मंहगाई सबसे बड़ी समस्या के रूप में स्थापित हो चुकी है। छोटे से छोटा आदमी भी मंहगाई से परेशानी अनुभव कर रहा है और बड़ा से बड़ा आदमी भी। पान दुकान में भी मंहगाई पर ही चर्चा केन्द्रित है और हवाई जहाज में भी। मुझे तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं जो मंहगाई से त्रस्त न हों। वैसे तो स्वतंत्र भारत के साठ वर्षों में हमेशा ही मंहगाई से परेशानी अनुभव की गई, किन्तु चुनावों के समय आम आदमी को यह अनुभव और दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही या तो महसूस होने लगता है या महसूस कराने की परंपरा रही है। इस वर्ष भी मंहगाई का एक भूत के रूप में स्थापित होना यह सिद्ध करता है कि अवश्य ही आम चुनाव बहुत नजदीक हैं।

मेरे अपने साथी भी मंहगाई से त्रस्त हैं। कुछ साथी तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। वे न मंहगाई की परिभाषा करना चाहते हैं न विरुद्ध में कोई बात सुनना चाहते हैं। बस टी. वी. में बड़ी मंहगाई का सरकारी आँकड़ा सुनते ही उनकी कमर टूटने लगती है और उनका भाषण शुरू हो जाता है। फिर तो वे इस सम्बन्ध में कुछ सुनते ही नहीं। मुझे मंहगाई के सम्बन्ध में चर्चा में सुखद आश्चर्य हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति प्यारे लाल जी खंडेलवाल से अस्पताल में मैं मिलने गया और मंहगाई पर बात छिड़ गयी। उन्होंने स्वयं माना कि यह एक राजनैतिक हथकण्डा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में और विस्तृत विवेचना की। चुनाव वर्ष में मंहगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर संतुलित विवेचना से मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव ही उत्पन्न हुआ। अन्यथा काँग्रेसी कार्यकर्ता तक स्वीकार करता है कि वह मंहगाई से परेशान है।

प्रश्न उठता है कि मंहगाई की परिभाषा क्या है ? मुद्रा स्फीति और मंहगाई में फर्क क्या है ? मैंने पूर्व में भी बहुत गहन विचार किया था और अब पुनः गंभीरता से सोचा तो पाया कि मंहगाई एक अस्तित्व हीन शब्द है, जिसका कभी कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होता। वास्तविक शब्द तो है मुद्रा स्फीति जिसका अर्थ होता है नगद रूपया पर अघोषित कर और

प्रभाव सिर्फ उसी पर होता है, जिसके पास नगद रूपया हो, कल्पना करिये कि किसी व्यक्ति को एक दिन का वेतन सौ रूपया मिलता है, और उसे सौ रूपये मे दस किलो औसत वस्तुएँ प्राप्त होती रहती हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी मजदूरी तो एक सौ दस रूपया हो गई और मुद्रा स्फीति बढ़ने के कारण कुल वस्तुएँ दस किलो ही मिली, तो उसे मंहगाई महसूस होने लगती है और उसकी कमर टूटने लगती है, जबकि वेतन वृद्धि और मूल्य वृद्धि किसी मंहगाई के परिणाम न हो कर मुद्रा स्फीति के परिणाम हैं, और मुद्रा स्फीति का तब तक कोई प्रभाव नहीं होता जब तक मूल्यों के अनुपात मे उसका वेतन बढ़ता रहे। इस तरह मंहगाई न कभी आई है न आयेगी, क्योंकि वेतन वृद्धि के अनुपात में मूल्य वृद्धि हमेशा ही कम रही है। स्वतंत्रता के बाद यदि आज तक का ऑकलन करें भी, तो मुद्रा स्फीति करीब सत्तर गुनी बढी है, जबकि मजदूरी डेढ सौ गुनी और कर्मचारियों का वेतन करीब तीन सौ गुना बढ़ा है। इसके बदले मे सोना-चौंदी, जमीन अधिक बढ़ा है। दालें, खाद्यतेल, कृत्रिम उर्जा आदि स्थिर हैं। अनाज, कपडा आदि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती हुई हैं, और टेलीफोन, रेडियो, घडी आदि तो कौडियों के भाव बिक रहे हैं। सोचने की बात है कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी कौन सी वस्तुएँ मंहगी हुईं जिनसे आम लोगो की कमर टूट गई। खाद्य पदार्थ और कपडा तो सस्ता हुआ है और सोना-चौंदी, जमीन मंहगी होने से किसी आम आदमी की कमर टूटती नहीं। फिर इतना हल्ला क्यों ? हल्ला इसलिए नहीं होता है कि मंहगाई से जन-जीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पडा है। हल्ला तो इस बात का होता है कि व्यक्ति को आज जो सुविधा प्राप्त थी, उसमे कोई कटौती हो रही है। यदि दस वर्ष पहले फोन का चार्ज दस रूपये था और आज एक रूपया है तो ठीक है। यदि कल दो रूपया हो जाय तो फोन भी मंहगा घोषित हो जायगा और मंहगाई मे शामिल हो जायगा। मैं तो साठ वर्ष पूर्व भी मंहगाई का ऐसा ही प्रचार और हल्ला सुनता था और आज भी वैसा ही है। मुझे तो हल्ले मे कभी फर्क नहीं दिखा। फिर भी इस बार की मंहगाई का कुछ अलग प्रभाव है। इस बार ऐसी वस्तुएँ मंहगी हुई हैं, जो आम आदमी के उपयोग की हैं जैसे-अनाज, दाल, खाद्यतेल आदि। किसी वस्तु के मंहगा होने के चार कारण हो सकते हैं—1. मुद्रास्फीति बढे 2.— वस्तु का उत्पादन कम हो 3.— वस्तु का निर्यात अधिक हो 4.— वस्तु का उपयोग अधिक होने लगे। मुद्रास्फीति का प्रभाव होता नहीं क्योंकि आम तौर पर मुद्रा स्फीति की तुलना मे वेतन भी अधिक बढ़ता रहा है और श्रम मूल्य भी। जो लोग कहते है कि आज वस्तुओं के मूल्य बढे हैं, और वेतन छः माह बाद बढेगा तब तक तो उस आदमी का कचूमर ही निकल जायगा। वे बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि यह कैसे माना गया कि वेतन पहले बढ़ा कि मूल्य। यदि मैं कहूँ कि छः माह पूर्व वेतन बढ़ा और आज मूल्य तो इस में गलत क्या है। अन्डा पहले कि मुर्गी यह विवाद न कभी सुलझा है न कभी सुलझेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत की कुल विकास दर नौ प्रतिशत है, जो सम्पन्नों की सत्रह प्रतिशत और बिल्कुल गरीबों की एक प्रतिशत करीब है। यदि मुद्रा स्फीति के प्रभाव से गरीब आदमी को आज ग्यारह प्रतिशत सामान कम मिल रहा है, तो विकास दर का उस व्यक्ति पर कितना प्रभाव पडता है ? अर्थात वह गरीब आदमी ग्यारह प्रतिशत मंहगाई के बाद भी विकास कर रहा है या उसका जीवन स्तर ग्यारह मे एक घटकर दस प्रतिशत नीचे जा रहा है।

यदि हम वस्तु के उत्पादन की कमी की बात करें तो जिन वस्तुओं की भारी मूल्य वृद्धि हुई है उनके उत्पादन में कोई विशेष कमी नहीं आई है। यदि हम मॉग वृद्धि और क़य वृद्धि की सोचें तो गेहूँ-चावल, दाल, खाद्यतेल की मॉग वृद्धि या क़य बढ़ने से कोई सम्बन्ध नहीं। सीमेंट और लोहा का इससे आंशिक संबंध है। यदि हम आयात निर्यात पर गंभीरता से विचार करें तो मंहगाई का सारा खेल इसी पर निर्भर है। सरकार कठपुतली के समान आयात निर्यात को नचाती रहती है, जिसका प्रभाव मूल्यों पर पडता है। सरकार साम्यवादियों को नाराज नहीं करना चाहती और साम्यवादी खाडी देशो के हितो की भारत में लम्बे समय से देखभाल करते रहें है। भारत में डीजल पेट्रोल के मूल्य न बढे, इन सबकी खपत कम न हो, इन सबका आयात भी कम न हो इसकी सर्वाधिक चिन्ता ये बिचारे वर्षों से पूरी ईमानदारी से करते रहे हैं। इस कार्य के लिए तो ये लोग सरकार तक को कुर्बान करने के लिये तैयार रहते हैं, और आप रोज-रोज का विवाद सुन भी रहें होंगे कि बिजली की उपलब्धता बढ़ने से होने वाले डीजल पेट्रोल के दुष्प्रभाव के लिए बेचारे कितना संघर्ष कर रहें हैं। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं है। अब आप विचार करिये कि यदि डीजल पेट्रोल की खपत कम नहीं करनी है, तो आयात करना ही होगा और उसी मुताबिक दुग्ने-चौगुने मुँह मॉगे दाम भी उन्हें चुकाने होंगे और उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्यात भी करना होगा। भले ही भारतीय जनता पर

उसका कुछ भी और कितना भी प्रभाव क्यों न पडता हो। यही और सिर्फ यही एक मात्र कारण है, जिसके कारण इस बार कुछ आवश्यक वस्तुओं के दाम इस तरह बढ़े हैं। साम्यवादी इस सहायता के लिए खाडी देशों से धन लेते हैं या नहीं यह बात तो नहीं मालूम किन्तु अन्य दलों को इस तेल के खेल से धन मिलना अब कोई छिपी बात नहीं। इस तरह धन के मामले में तो सबकी सहानुभूति खाडी देशों के साथ रहती ही है और बदनाम बिचारे अकेले वामपंथी रहते हैं क्योंकि खाडी देशों को अमेरिका के विरुद्ध खड़ा रखना भी तो आसान काम नहीं है।

मेरे विश्लेषण अनुसार मंहगाई का कोई अस्तित्व न होते हुए भी काँग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने ही तो सिर्फ प्याज और टमाटर की मंहगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव जीत लिया था। अब यदि यह मुद्दा उसके विरुद्ध जा रहा है, तो वह किस मुँह से वास्तविक तर्क समाज के समक्ष रखे और कौन उस बात को सुनेगा ? कुछ आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का दोष भी काँग्रेस आयात-निर्यात की अपनी नीति को नहीं दे सकती, क्योंकि उसे भी चुनाव लड़ना है और यह आयात-निर्यात ही तो उसके लिए जर्सी गाय का काम करती है।

सरकारी कर्मचारी यह पोल खोलने को तैयार नहीं क्योंकि मंहगाई का प्रचार उन्हें कई गुना अधिक वेतन बढ़वाने में सहायक होता है। अन्य अनेक पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता इस असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं। उन्हें न मंहगाई का पता है न तेल के खेल से कुछ लेना देना है। जो हल्ला समाज में उठ रहा है उसके साथ अपने को जोड़ लेना उनकी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि मंहगाई के मुद्दे पर समाज में व्यापक विचार मंथन हो और सच समाज के समक्ष प्रकट हो।

प्रश्न: 2— आप का क्या होगा जनाब—ए—आली :- प्राकृतिक नियम है कि जो चीज जल्द बनती है वह उतनी ही जल्द बिगड भी जाती है। बुलबुला झण भर में मिट जाता है, जबकि पत्थर के बनने और बिगडने में सदियों लग जाती है। कोई झांसाराम बहुत दिनों तक आसाराम नहीं बना रह सकता। “उघरहिं अंत न होई निबाहू—कालनेमि जिमि रावन राहू” के अनुसार निश्चित समय आने पर पाखंड खंडित हो ही जाता है और ढोंग की पोल खुल ही जाती है। आम आदमी पार्टी के बारे में भी धारणा बनाने में जल्दवाजी नहीं करनी चाहिये। इसे दिल्ली-प्रदेश की सत्ता में आये अभी जुमा-जुमा चार दिन भी नहीं हो पाये हैं और अभी से इसकी कलई खुलने लगी है। अन्ना द्वारा उछाले गये अति सामयिक भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपना हथियार बनाकर केजरीवाल ने सफलता प्राप्त की उन्ही का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा—यह तो अन्ना का जोकपाल है। भयंकर मंहगाई आदि के कारण तत्कालीन वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष, नये प्रत्याशी को आजमाने की उत्कंठा तथा विदेशों में जमा काला धन लाने व सत्ता में आने पर कांग्रेसियों को तत्काल जेल भेजने जैसे लोक-लुभावन वादों-दावों के कंधों पर सवार होकर केजरीवाल सिंहासन तक पहुंचे। जिस कांग्रेस को यह भ्रष्ट कहते नहीं थके और जिसकी कब्र पर महल खड़ा किया उसी से गलबहियाँ करके इन्हे अब भ्रष्टाचार पर उपदेश देना शोभा नहीं देता। रही बात वादे निभाने की तो कोई भी वादा ऐसा नहीं है जिसके गड्डे को भरने के लिये पास की जमीन न खोदी जाये। वैसे भी क्या शीला को जेल भेजने के वारंट पर यह शीला के ही हस्ताक्षर करवा लेंगे। शायद ऐसा हास्यापद एवं मूर्खतापूर्ण गठबंधन संसार में दूसरा न होगा। वस्तुतः यह गठबंधन नहीं ठग-बंधन है जिसका एक ठग सत्ता का भूखा था और दूसरा ठग रक्षा का। अब तो केजरी और कांग्रेस को चोर-चोर मौसेरे भाई कहना चाहिये। वैसे भी जब तक बेइमानी करने का मौका नहीं मिलता तब तक हर बेइमान ईमानदार ही होता है। रामलीला मैदान में शपथ की नौटंकी करना, उसके लिये मेट्रो से आना ये सब ढोंग थे। रामलीला मैदान में ही यदि इस प्रकार के झूमे होने लगे, तो संसद और विधान मंडलों की क्या उपयोगिता रह जायेगी। रामलीला मैदान में नाटक करने वाला क्या हर आदमी अच्छा होता है, और लोकसभा एवं विधान सभा में शपथ लेने वाला हर व्यक्ति बुरा ? केजरी के नेतृत्व में प्रदर्शित सादगी का ढोंग अब भी बदस्तूर जारी है। इसी के कारण पहले केजरीवाल भगवान दास रोड स्थित 10 बड़े रूम वाले जिस भव्य आलीशान फ्लैट में रहने जा रहे थे, उसे छोड़कर उनसे अब नई दिल्ली के किसी छोटे फ्लैट में रहने की तैयारी की है। पूर्व निश्चित फ्लैट सुप्रीम कोर्ट के जजों एवं केंद्रीय मंत्रियों के फ्लैटों से भी बड़ा था। टोपी पहनकर प्रशासनिक कार्य सम्पन्न करना भी बचकानी मानसिकता का प्रतीक है। वह भी ऐसी जोकर ब्रान्ड टोपी है जो ना सीधी है और ना ही गोल। टोपी को सांगठनिक कार्यक्रमों

में तो पहना जा सकता है, पर विधानसभा के कार्यकलापों में पहनना मर्यादा का उल्लंघन है। मजमा जमाना कोई बड़ी बात नहीं है, जादूगर और बाजीगर इसे रोज करते हैं, पर शासन करना बहुत कठिन है। बजर-बटू से रूपया बनाने वाला बाजीगर वास्तव में रूपया बना लेता तो जगह-जगह भीख क्यों माँगता ? यह तो बस उसका ढोंग होता है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि मुख्यमंत्री की भारी सीट पर कोई हल्का आदमी भाग्य की बदौलत बैठ गया।

इनकी सबसे बड़ी झॉसों वाली बात यही है कि ये आम आदमी की बात करतें हैं, जबकि इनमें से तो कोई आम-आदमी नहीं है। दिल्ली में भी अधिकतर आम आदमी नहीं रहते। आम आदमी भारत के आठ लाख गाँवों में रहता है जिसे आज की तारीख में भी रोटी, कपडा और मकान के लाले पडे हुए हैं। इन्होंने पार्टी के नामकरण के द्वारा भी लोगों को मूर्ख बनाया है। आप (AAP) आम आदमी पार्टी का संक्षिप्त अंग्रेजीकरण है। इसका हिन्दीकरण भाजपा, माकपा, बसपा, सपा, की तरह "आ-आ-पा होना चाहिए। आप में अंग्रेजियत याने परराष्ट्रवादिता की बू है। इतना ही नहीं कश्मीर में जनमत संग्रह करने की बात कहकर आपने इससे भी आगे जाकर अराष्ट्रवादिता याने राष्ट्रद्रोह का कार्य कर डाला। कश्मीर जैसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर आपको क्षमा नहीं किया जा सकता है। यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि राष्ट्रवादिता के मामले में जो भी यहाँ नया आता है, वह घाघ होता है और पुराने का बाप निकलता है। एक सॉपनाथ होता है तो दूसरा नागनाथ। अभी तो वह ढंग से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पायें हैं, और इतने एक्सपर्ट क्वालिटी का तुष्टीकरण शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने इसी नीति और नीयत के तहत अभी बरेली की आला हजरत की मजार पर चादरपोशी भी कराई है। इतना ही नहीं केजरीवाल चुनाव से पूर्व बरेली में एक मुस्लिम नेता से मिले थे जो बरेली में 2012 के दंगा का प्रमुख माना जाता है तथा जिसके कारण दंगा में लोग भी मारे गये। अरबों-खरबों की सम्पति स्वाहा हुई तथा 22 दिन तक वहाँ के घरों में चूल्हे नहीं जले थे।

सबसे अहम बात यह है कि आप की कोई साँस्कृतिक विचारधारा नहीं है। यह केवल पेट को महत्व देती है, आत्मा को नहीं। समाज, मानवता के उन्नयन हेतु इसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। अस्तु तय है कि इससे केवल साम्यवादी दलों को ही खतरा है, अन्य दलों को नहीं या न के बराबर। पर अभी तो यही देखना है कि आगे क्या-क्या होता है।

उत्तर:—आपके विषय में हम लोगों के बीच में यह धारणा बनी हुई है, कि आप आँशिक रूप से ही किसी ओर झुक सकते हैं, एकपक्षीय रूप से तर्कहीन तरीके से नहीं। आपके अरविंद केजरीवाल संबंधी लेख ने मेरी इस धारणा को तोड़ा है। तीन लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री की दौड़ में दौड़ रहे हैं। जिसमें सबसे आगे तो नरेंद्र मोदी ही हैं, दूसरे नम्बर पर कभी राहुल गाँधी दिखने लग जातें हैं, कभी अरविंद केजरीवाल। आपने जिस तरह अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है, उससे संदेह होता है कि आप नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। किसी का प्रशंसक होना कोई बुरी बात नहीं है किन्तु प्रशंसक होने का यह मतलब नहीं है, कि दूसरे पक्ष की आलोचना में विरोध झलकने लगे। अपनी पहचान तटस्थ समीक्षा की दृष्टि में आठ आधारों पर बनती है। या तो आप तटस्थ समीक्षक हों या प्रशंसक-समर्थक, सहयोगी-सहभागी, दूसरी ओर समीक्षक के बाद आलोचक-निंदक, विरोधी और शत्रु तक बढ़ा जा सकता है। अब तक मैंने आपको समीक्षक से बढ़कर या तो मोदी जी का प्रशंसक की सीमा तक बाँधा था या शेष दोनो के अर्थात् अरविंद केजरीवाल तथा राहुल गाँधी के आलोचक तक। किन्तु इस लेख के द्वारा आपने सीमाएँ तोड़कर अरविंद केजरीवाल की एक पक्षीय निंदा—जो बढ़ते-बढ़ते विरोध तक चली गई है दिखी। हमें इस प्रकार के विचारों से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हमें यह तय करना पड़ता है, कि हमें किस भाषा में उत्तर देना है, यही कारण है कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ।

स्पष्ट घोषित है कि मैं लोकस्वराज्य और तानाशाही के बीच किसी भी सीमा तक लोकस्वराज्य के पक्ष में जा सकता हूँ। यही कारण है कि मैं अन्ना जी के समर्थन में खड़ा दिखता हूँ। मैंने अब तक अरविंद केजरीवाल में लोकस्वराज्य के प्रति साफ-साफ दृष्टिकोण नहीं देखा है। फिर भी मैंने इतना अवश्य देखा है कि नरेंद्र मोदी में तानाशाही स्पष्ट झलकती है। 2014 के चुनावों में कॉंग्रेस पार्टी को तो वोट देने का अर्थ ही नहीं है क्योंकि उसे वोट देना तो एक परिवार की गुलामी पर मुहर लगाना है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि यदि भगवान भी नेहरू परिवार में जन्म ले लें तो उनको भी प्रधानमंत्री बनाना गुलामी ही माना जाएगा। इसलिए

तीनो उम्मीदवारों में से राहुल गाँधी का सर्वाधिक प्रशंसक होने के बाद भी मैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के एकपक्षीय विरोध में हूँ। नरेंद्र मोदी में समस्याओं की समाधान की अद्भूत क्षमता है और यदि अरविंद केजरीवाल लोकस्वराज्य की दिशा में साफ-साफ नहीं बढ़ते हैं, तो वर्तमान चुनाव में भगवान भरोसे छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अनेक गलतियाँ करने के बाद भी मुझे अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त किसी अन्य में कोई उम्मीद नहीं दिखी, जो आँशिक रूप से भी, स्वराज्य की चर्चा करे। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप तर्कों के आधार पर अपनी बात रखने की अपनी छवि को बनायें रखें।

3. वासुदेव यादव एडवोकेट—व्यवहार न्यायालय देवरिया उ.प्र.।

प्रश्न:—आप द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। आपके द्वारा भेजा जा रहा ज्ञानतत्व बराबर मिलता है, और मिलने के तुरन्त बाद सब काम छोड़कर ज्ञानतत्व को पढते हैं। आपके द्वारा चलाया जा रहा अभियान बहुत सराहनीय है तथा उसमें जो चर्चाएँ आती हैं, वह भी अच्छे विद्वानों द्वारा लिखा गया होता है। एक बात जरूर मेरे मन में पैदा होती है कि जहाँ देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अपराधी जगह-जगह हावी है और सत्ता में बना हुए हैं, जिसको जेल में होना चाहिए वह पुलिस अभिरक्षा में घूम रहा है। किसान, गरीब, देश के नौजवान मारे-मारे फिर रहें हैं, उनके लिए उनकी सरकार कब आयेगी? वे कैसे लोग होंगे जिन्हें सत्ता प्राप्ति के पहले चिन्हित नहीं किया जा सकता? आप उत्तर-प्रदेश सरकार के संबंध में ज्ञानतत्व में कभी टिप्पणी नहीं करते, जहाँ पर विकास ठहर सा गया है। एक मात्र चीनी उद्योग समाप्त होने के कगार पर है। यहाँ के नेता जातिवाद फैलाकर सत्ता को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। क्या इनके विरुद्ध कोई अभियान चलेगा?

उत्तर:— एक ओर तो आपने विकास की चर्चा की है, दूसरी ओर अपनी सरकार की चर्चा की है। यदि सरकार विकास करेगी तो शासक और शासित के बीच की दूरी बढ़ेगी ही। सरकारों का काम विकास करना नहीं होता बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जिसमें सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी-अपनी क्षमतानुसार विकास कर सकें। सरकार किसी की ऐसी स्वतंत्रता में न बाधा पैदा कर सकती है न किसी की सहायता। आपने उत्तर-प्रदेश सरकार की समीक्षा चाही है तो आप बताइये कि मैं उत्तर-प्रदेश सरकार की, झारखण्ड की तुलना में आलोचना करूँ अथवा बंगाल की अथवा तमिलनाडू की या और किसी की। मैं ये नहीं कर पाता हूँ कि कौन प्रशंसा करने योग्य है और कौन आलोचना करने योग्य। मनमोहन सिंह ने लीक से हटकर कुछ स्वतंत्रता देने की पहल की तो मनमोहन सिंह की दुर्गति आप देख रहे हैं। नीतिश कुमार ने बिहार में कुछ अच्छी पहल की तो उनका भी हाल आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तानाशाही तरीके से समस्याओं का समाधान किया तो वे प्रधानमंत्री पद के निकट पहुँच गए हैं। ऐसे स्थिति में सिर्फ उत्तर-प्रदेश की बात करना मेरे लिए कितना उचित होगा।

4. के विठ्ठल राव—मैसूर कर्नाटक।

प्रश्न:—आपकी पत्रिका ज्ञान तत्व 282 प्राप्त हुआ। ज्ञान तत्व में प्रकाशित—“राजनीति में राहुल गाँधी” लेख पढा। प्रस्तुत राजनीति की हालत में आपने एक प्रभाव पूर्ण लेख लिखकर कलम रूपी तलवार से आम जनता पर वार किया है। ऐसा निर्भय लेख किसी प्रांतीय भाषा की पत्रिका या अंग्रेजी पत्रिकाओं में देखा नहीं। इसलिये इस लेख को कर्नाटक राज्य की भाषा में अनुवाद करना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो ऐसा कर सकता हूँ। इस कारण से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अनुवाद करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

उत्तर:—ज्ञान तत्व में जो भी मेरे विचार प्रकाशित होते हैं, वे मेरी धरोहर नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण समाज में विचार मंथन के लिये है। यदि कोई व्यक्ति उनसे सहमत या असहमत होकर उन विचारों को कहीं पुनः प्रकाशित करना चाहता है, तो मुझे खुशी होगी। यहाँ

तक कि कोई व्यक्ति उन विचारों को अपने नाम से भी प्रचारित करना चाहे तो मेरे लिये किसी प्रकार के कष्ट, आपत्ति अथवा अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे नाम से प्रकाशित हो तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

आपको मालूम ही होगा कि मैं एक विचारक हूँ जिसे प्रचार से अधिकतम दूरी बनाकर रखनी चाहिये, क्योंकि प्रचार—विचार विस्तार में सहायक होता है, विचार मंथन में बाधक। मैं पांच वर्ष दिल्ली में रहा, मेरी प्रसिद्धि बढी किन्तु चिंतन की क्षमता घटी। मैंने इसे सामाजिक क्षति माना और मैंने साथियों के रोकने के बाद भी दिल्ली से वापस लौटना उचित समझा। कुछ साथियों को मेरा यह निर्णय गलत भी लग सकता है, किन्तु मैं समझता हूँ कि मेरा निर्णय सही था।

अंत में मैं अनुमति के साथ—साथ यह निवेदन करता हूँ, कि आप उक्त लेख अथवा ऐसे किसी विचार को पुनः प्रसारित करें।

5. बंसन्ती लाल सरूपरिया— एडवोकेट राजसमंद राजस्थान।

प्रश्न:—आपके द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति श्री राहुल जी एवं श्रद्धेय श्री मोदी जी के संबंध में दी है। यह एकदम सही है। भगवान ने चाहा तो सन 2014 में अगर भारत वर्ष का प्रधान मंत्री श्रद्धेय मोदी जी बनते हैं, तो पूरे भारत वर्ष को लाभ मिलेगा क्योंकि इतने लम्बे समय से देश में ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो भारत वर्ष को चला सके। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था। उसकी एक प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेज रहा हूँ। कृपया अवलोकन करके आने वाले समय में श्री मोदी जी का व्यवहार अच्छा रहेगा या नहीं इस बात का जबाब अवश्य भेजें।

मोदी जी द्वारा दिनांक 15/8/2013 को दिये गये भाषण से मुग्ध होकर, यह पत्र लिखने के लिये मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिये विवश होना पडा।

टी. वी. पर मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मोदी जी का पूरा भाषण सुना। उस भाषण से यह सार निकला कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति की भारत को सख्त जरूरत है और ऐसे व्यक्ति ही देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। भाषण के दौरान उन्होंने राजनैतिक, आर्थिक और औद्योगिक नीतियों पर जो बातें रखीं, उनकी आज की देश की परिस्थितियों को देखते हुए उन जैसे प्रधान मंत्री के रूप में जनता को मिलना अति आवश्यक है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि उनके भाषण को सुनने के लिये पब्लिक के लिये टिकट की व्यवस्था की गयी थी। भारत देश के लिये ऐसा व्यक्ति विरला ही पहली बार भारत में हुआ है। मोदी जी को भाजपा का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना एक सौभाग्य की बात है। हरियाणा की वीर धरा रेवाड़ी में राजग के प्रधान मंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी की हुई रैली में पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व सेना कर्मचारी व लाखों लोगों की भीड़ जुटने से राष्ट्र स्वाभिमान की स्पष्ट झलक दिखाई दी। जिस तरह जनता ने भारत माता की जय व मोदी जिंदाबाद के नारे लगाये उससे साफ हो गया कि मौजूदा केन्द्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से आहत लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और सशक्त नेतृत्व के हाथों देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। यह रैली एक ऐतिहासिक रैली थी। भाजपा के पी एम पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी जी की दिल्ली में जो रैली हुई उसमें जनता अपनी श्रद्धा से आयी थी, न की भाडे पर जनता इकट्ठी की गयी। इस अपार जन समूह विशेषकर युवा शक्ति को देखते हुए आज उन जैसे प्रधानमंत्री की भारत देश को आवश्यकता है, जो वे हासिल करके रहेंगे। आज प्रत्येक नागरिक को उन पर नाज है, कि उन जैसे विद्वान, सुभाषी, राष्ट्र प्रेमी के रूप में पदासीन हो यही जन आकांक्षा है। उन्होंने कहा कि “मैं शासक नहीं मुझे तो सेवक के रूप में काम करना है” यह कितना बड़ा सोच है जो उन्होंने प्रकट किया।

उन्होंने अपने संबोधन में व्यक्त किया था कि मनमोहन जी को बोलने की आदत नहीं रही है। वे भूल गये कि क्या और कैसे बोलना है। यह युक्ति बिल्कुल चरित्रार्थ हुई कि उन्होंने नवाज शरीफ के सामने आम बातों के अलावा और कुछ नहीं कहा। उनका आत्म विश्वास इतना तगडा है कि अच्छे—अच्छों को नत मस्तक होना पडता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम

पर जब श्री राजनाथ सिंह जी ने मोहर लगाई, उस वक्त पूरे भारत वर्ष में लोग भाव विभोर हो उठे। सबकी जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो गई, इसका सबूत दिल्ली के अंदर जो जनता इकट्ठी हुई थी, उस जनता ने टिकट खरीद कर मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण के दौरान जनता ने दिल्ली के अंदर जो सराहना की वह दृश्य सभी टी.वी. चैनलों पर देखा गया और श्रद्धेय मोदी जी की प्रशंसा लाखों लोगों द्वारा की गयी। मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन होंगे, यही हमारी अंतरात्मा की आवाज है।

उत्तर:—आपने सच ही लिखा है कि भारत की जनता विशेषकर उत्तर भारत की जनता का बहुमत मोदी जी के पक्ष में है। भावनात्मक रूप से मोदी जी के भाषण ने आम जनता को आकर्षित भी किया है और उत्साहित भी। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भीड़ का समर्थन अथवा भाषण की कला उचित-अनुचित का एकमात्र पैमाना होगा ? कुछ दिनों पहले आशाराम बापू का जादू छाया हुआ था। अब भी बहुत लोग उस मोहपाश से नहीं उबर पायें हैं। कुछ माह पहले तक तो बाबा रामदेव अथवा निर्मल बाबा भी भगवान से कम नहीं माने जाते थे, किन्तु आज उनका आकर्षण बहुत घट गया है। कुछ माह पूर्व तक अन्ना हजारे के पीछे भारत ही नहीं, सारी दुनिया पागलता की सीमा तक आगे बढ़ रही थी। आज किसी प्रकार की गलती ना करने के बाद भी उनके साथ चलने वाला एक भी साथी दिखाई नहीं देता। आप यदि नरेंद्र मोदी से इतने सम्मोहित हैं, तो यह आपका व्यक्तिगत विषय है, मेरा नहीं। अब तक नरेंद्र मोदी ने अपनी क्षमता तो प्रमाणित की है, किन्तु नीयत का कोई प्रमाण सिद्ध नहीं किया है, बल्कि उनके आचरण से उनकी नीयत पर कुछ-कुछ संदेह ही होता है। इतिहास बताता है कि हिटलर के पीछे भी जर्मनी इसी प्रकार पागल हुआ जा रहा था, किन्तु परिणाम हमने देखा कि वह पागलपन उसे किस सीमा तक ले गया। मेरा सुझाव है कि आप नरेंद्र मोदी को भारत भाग्य विधाता भलें ही मान लें किन्तु मुझ जैसे व्यक्ति को अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने दें। वैसे इसी अंक में एक लेख लिखकर मैंने आपके प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया है।

6. शिवदत्त बाघा— बॉदा उत्तर—प्रदेश।

प्रश्न:—दुनिया उलझी हुई है या उलझाई गई है। दुनियाँ बँटी हुई है या बॉटी गई है—इन्हीं दो बातों को लेकर वादों—विवादों के अनेकानेक संस्करण सामने हैं। वाद—विवाद है, प्रश्न है, असल मुद्दे गायब हैं। “जिमि पाखण्ड विवाद से लुप्त होंहिं सदग्रन्थ” अर्थ यह है कि सत्य गायब है। भौतिक जगत का भौतिक सत्य है सत्ता, शासन, सरकार। शासन का उद्देश्य क्या है ? इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने कौन से मूल्य तय किये हैं। सत्ता के संदर्भ में ये दो बातें ही महत्वपूर्ण हैं, शेष बकवास जान पड़ती है। विद्वत समाज अपना विद्वता का कीमती समय इन्हीं मिथ्या बातों में जाया कर रहा है, फिर इस धरती को इन्सानों के रहने लायक बनाने की कोई राह बनती नहीं दिख रही। सरकारों, सत्ता, शासन का भी एक मात्र उद्देश्य यही था कि वह धरती को इन्सानों के रहने लायक बनाने में मानव जाति का सहयोग करे, संरक्षण करें। पर दुनिया की सारी हुकुमतें उल्टी दिशा में चल निकली जिससे बहसों को जन्म मिला। इस पाखण्डपूर्ण बहस व आचरण में वह बेचारा व्यक्ति अथवा मानुष जो सारी धारणाओं, विचारों के केन्द्र में था, कल भी बेचारा था और आज भी बेचारा है। इस प्रकार बेचारे बनाये गये लोगों की सीढी ही सत्ता प्रेमियों को सत्ता तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। अर्थ यह है कि इन बेचारों के कंधों पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचा जायेगा और अपनी हसरतों को पूरा किया जायेगा। इन्हीं बेचारों के भरोसे इन्हीं के नाम जनतंत्र से वह सब कुछ हासिल होगा, जो सत्ता मंडली को चाहिये होगा। “गधो पर बोझ ढोते हैं शेरों पर नहीं”। इसी संदर्भ में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सूरज निकलने से पहले उसके निकलने का आभाष होने लगता है। इसी प्रकार किसी के नेक इरादों की झलक उनके सामने आने से पहले ही दिखाई देने लगती है। हम अपने देश की व्यवस्था के अब तक के सफर में नेक—नीयती की झलक का अभाव ही देख रहे हैं। जैसी भटकाव की स्थिति अपनी व्यवस्था के सामने है और जैसी चतुराई एक राजनीतिक दस्तावेज के जरिये भटकाव की पैदा की गयी है, उसके देखे भटकाव से उबरने की आशा नगण्य है। राजनीति के इस दलदल में प्रत्येक भटका हुआ आदमी खुद को रास्ते पर और दूसरों को भटका हुआ बता रहा है। अभी जनवरी के प्रथम सप्ताह में मीडिया से रूबरू देश के प्रधानमंत्री जी का कथन अगर “नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बने तो देश में तबाही मच जायेगी” कितना विश्वसनीय है।

एक तरफ संविधान कानून के राज दुहाई दूसरी तरफ एक व्यक्ति के आने से तबाही इन दो विरोधी बातों में सच कौन सी है। यह पक्ष प्रश्न हमारी व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रणाली संविधान कानून के शासन की घोषणाओं को अविश्वसनीय बना देता है, नाजुक ठहराता है। माना कि इस मुल्क में किसी के लिये यह गुंजाइश है कि वह अपनी मर्जी की हुकुमत चला सकता है अथवा कायम कर सकता है। यह देश 66 वर्षों से इसी मर्जी को झेल रहा है। लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे। इसी लिये हम किसी और के लिये उसकी मर्जी का हौवा खड़ा कर रहे हैं मतलब यह कि न अब तक हम लोकतंत्र में थे न आगे रहेंगे। हम किसी की मर्जी झेलने के लिये ही अभिशप्त हैं। आपका लोक स्वराज्य आंदोलन भी कुछ ऐसी ही गवाही दे रहा है। कि हम लोकतंत्र की बजाय किसी की मर्जी के दास हैं।

उत्तर:— आपने जो लिखा है, उसमें दुनिया की वर्तमान हालत सहित भारत की वर्तमान हालत का एक सजीव चित्रण है, जो आमतौर पर साधारण नागरिक से लेकर आप विद्वान तक करते मिल जाते हैं। किन्तु आपके इतने लम्बे लेख में न किसी एक समस्या के समाधान का मार्ग दिखा न अनेक समस्याओं के एक साथ समाधान का। आपके पत्र ने निराशा जनक अंधेरा तो बढ़ाया है, परंतु सूर्योदय होने का कोई आभास तक नहीं कराया, तो मैं आपके पत्र की क्या समीक्षा करूँ। नरेंद्र मोदी— मनमोहन सिंह को अक्षम सिद्ध करने में दिन—रात लगें हुए हैं, और मनमोहन सिंह ने पलटकर नरेंद्र मोदी के आने से होने वाली तबाही की भविष्यवाणी कर दी, तो इस राजनीतिक दौड़—पेंच में हम आपको क्यों उलझना चाहिए। इसलिए मैं आपके पत्र की कोई समीक्षा नहीं कर रहा हूँ किन्तु इसी अंक में प्रकाशित मेरे लेख की आप समीक्षा करेंगे तब मैं विचार—मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा।